

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38. सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 जून 2014— आषाढ़ 9, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3. — यतः भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा-5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उल्लिखित “नियुक्ति के लिए पात्रता” संबंधी प्रावधान में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 17-01-2012 द्वारा उपांतरण करते हुए, निर्देशित किया गया था कि इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों के मात्र स्थानीय निवासी ही, उक्त अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये, संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे ;

और यतः उक्त अधिसूचना 17 जनवरी, 2012 को दो वर्ष की कालावधि के लिए जारी किया गया था और 16 जनवरी, 2014 तक प्रवृत्त था ;

और यतः यह आवश्यक हो गया है कि उक्त अधिसूचना की अवधि, आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई जाये ;

अतएव, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा-5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निर्देशित करते हैं कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उक्त अधिसूचना द्वारा किया गया उपांतरण, आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए निरंतर प्रवृत्त रहेगा अर्थात् 17 जनवरी, 2014 से 16 जनवरी, 2015 तक प्रवृत्त समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2014

क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 19 मई, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव

Naya Raipur, the 19th May 2014

NOTIFICATION

No. F 1-1/2012/1-3. — Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-para (1) of Para 5 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, modifying the provision regarding "eligibility for appointment" mentioned in rule 5 of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 made by the State Government under Article 309 of the Constitution of India vide Notification No. F 1-1/2012/1-3, Dated 17-01-2012, directed that notwithstanding anything contained in these rules or any other Act, Order, Direction, Rules or Law for the time being in force, only local residents of the districts falling under Bastar and Sarguja Division, shall be eligible for recruitment to the vacancies arising in Class-III and Class-IV posts of the district cadre in various departments of the concerned districts, for a period of two years from the date of issue of the said Notification ;

And Whereas, the said notification was issued on 17th January, 2012 for a period of two years and was in force till 16th January, 2014 ;

And Whereas, it has become necessary to extend the term of the said notification for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-para (1) of Para 5 of the Fifth Schedule, the Governor of Chhattisgarh, hereby, directs that the modification made by the said notification in the rule 5 of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 shall remain continuously in force for a further period of one year i. e. from 17th January, 2014 to 16th January, 2015.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.